पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित किया

पिछले साढ़े चार वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है : मुख्यमंत्री

आजादी के बाद पहली बार किसी केन्द्र सरकार के एजेण्डे में किसान को शामिल किया गया है : मुख्यमंत्री

किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान केन्द्र सरकार ने किया

किसानों को बड़ी संख्या में स्वॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये

इसके अलावा उन्हें बीज, खाद, नीम कोटेड यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए गए, ताकि उन्हें इसके लिए भटकना न पड़े : मुख्यमंत्री

भारत सरकार के प्रयासों से यूरिया की कालाबाजारी रुकी

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कदम उठाए गये

लघु एवं सीमान्त किसानों के 01 लाख रु0 तक के फसली ऋण की कर्जमाफी प्रमुख निर्णय

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ की फसलों के समर्थन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिल रहा है : मुख्यमंत्री

वर्ष 2017–18 में किसानों से 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान सीधे उनके खातों में पहुंचाया गया

वर्ष 2017–18 में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी

बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों से आलू खरीदने की व्यवस्था की गयी

वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 37,035 करोड़ रु0 के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, जो अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है : मुख्यमंत्री

बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को 4,000 करोड़ रु0 का सॉफ्ट लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा

प्रत्येक जनपद को गौशाला की स्थापना के लिए
01 करोड़ 20 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है

मनरेगा को खेती से जोड़े जाने के लिए गठित समिति किसानों के सभी सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है

केन्द्र सरकार 10 वर्ष से अधिक पुराने ट्रैक्टर इत्यादि जैसे डीजल वाहनों के संचालन पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी रोक के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका शीघ्र ही दाखिल करेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, राज्य सरकार उसे हासिल करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है

लखनऊ : 02 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों से देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी केन्द्र सरकार के एजेण्डे में किसान को शामिल किया गया है, ऐसा उनके कार्यकाल के दौरान किसानों के हितों में लिए गये विभिन्न निर्णयों/कार्यों से साबित भी होता है। किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान केन्द्र सरकार ने किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा उन्हें बीज, खाद, नीम कोटेड यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करायी गयी है, ताकि उन्हें इसके लिए भटकना न पड़े। भारत सरकार के प्रयासों से यूरिया की कालाबाजारी रुकी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कदम उठाए गये हैं। इसमें लघु एवं सीमान्त किसानों के 01 लाख रुपये तक के फसली ऋण की कर्जमाफी प्रमुख हैं। इससे 86 लाख किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, किसानों के हित में सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, मूल्य समर्थन योजना आदि भी संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ की फसलों के समर्थन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फसली वर्ष 2018—19 कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड—ए धान का समर्थन मूल्य 1770 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा धान की उतरायी, छनाई, सफाई आदि खर्च के मद में किसानों को अधिकतम 20 रुपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जाएगा, जो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। वर्ष 2017—18 में किसानों से 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान सीधे उनके खातों में पहुंचाया गया है। इस वर्ष 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गयी है। किसानों को राहत देने के लिए 01 अक्टूबर, 2018 से धान क्रय की शुरुआत हो गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए अभियान चलाकर गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों से आलू खरीदने की व्यवस्था भी की गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत वर्ष और इस वर्ष अब तक वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 37,035 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, जो अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। इसमें वर्ष 2017—18 का 26,435 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान भी शामिल है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016—17, 2015—16, 2014—15 सहित इससे भी पुराने वर्षों का कुल 10,600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 5,535 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए इस धनराशि से चीनी मिलों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेराई सत्र 2016—17 एवं 2017—18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को 4,000 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 1,010 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गयी है। निगम

क्षेत्र की चीनी मिलों को 25 करोड़ रुपये की ऋण सहायता बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु प्रदान की गयी है। यह सभी धनराशि सीधे कृषकों के खाते में उनके बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के सापेक्ष भेजी जायेगी। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने आवारा पशुओं की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद को गौशाला की स्थापना के लिए 01 करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। इनकी स्थापना हो जाने के उपरान्त बड़ी संख्या में आवारा पशुओं को यहां पर रखा जा सकेगा। इन पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा देने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़े जाने के लिए गठित समिति किसानों के सभी सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार 10 वर्ष से अधिक पुराने ट्रैक्टर इत्यादि जैसे डीजल वाहनों के संचालन पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी रोक के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका शीघ्र ही दाखिल करेगी, ताकि इससे सम्बन्धित किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों ही किसानों की समस्याओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील हैं और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, राज्य सरकार उसे हासिल करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक सुनकर उनका समाधान निकाल रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों का मुनाफा बढ़ाने की दृष्टि से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों की सुविधा के लिए गांवों को 18 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। गन्ना किसानों की सुविधा के लिए बन्द पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें निरन्तर किसानों के हित में कार्य कर रही हैं। उन्होंने किसानों से कानून–व्यवस्था बनाए रखने को कहा।

————————